भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *140

उत्तर देने की तारीख: 04.12.2024

'पढ़ो परदेश' जैसी योजना की पुन:शुरुआत

***140. सुश्री इकरा चौधरी:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अल्पसंख्यक छात्रों के समक्ष आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक प्रभावी लक्ष्य तंत्र वाली 'पढ़ो परदेश' जैसी योजना पुन:शुरू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह मूल्यांकन किया है कि क्या अन्य मंत्रालयों की योजनाओं से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विदेश में शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) विदेश में शिक्षा प्राप्त करने में अल्पसंख्यक छात्रों के समक्ष आने वाली सामाजिक और वित्तीय बाधाओं को दूर करने वाली लक्षित और गैर-अतिव्यापी (नॉन-ओवरलैपिंग) योजना बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

''पढ़ो परदेश' जैसी योजना की पुन:शुरुआत' के संबंध में सुश्री इकरा चौधरी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *140 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और पढ़ो परदेश योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को कम ब्याज दर पर विदेश में शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण प्रदान करता है। यह भी देखा गया कि पढ़ो परदेश योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का लाभ सीमित था और यह अन्य मंत्रालयों जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य समान योजनाओं के साथ ओवरलैप भी है, जो पात्र अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए भी लागू हैं। उपर्युक्त ओवरलैप, सीमित लाभ और कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहजता को देखते हुए, 2022-23 से पढ़ो परदेश योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल, पढ़ो परदेश योजना को पुन: शुरू करने या इसके समान कोई नई योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****